जीवन में तकलीफ उसी को आती है, जो हमेशा जिम्मेदारी उठ को तैयार रहते हैं। -अज्ञात

विचार-प्रवाह
देहरादून, बुधवार, 18 अगस्त 2021
पेज थ्री
www.page3news.in

मुफ्त में टीके लगवाने का इंतजाम

लोगों को सरकार की ओर से किसी तरह की सुविधा या सामान मुफ्त देने की बात नहीं थी। यह उनका जीवन और स्वास्थ्य सुरक्षित करने का मामला था, जो उनका संवैधानिक अधिकार है। साफ है कि यह फैसला महामारी के खिलाफ जंग में मील का पत्थर साबित हो सकता है।

मोहन शर्मा।।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को मुफ्त में टीके लगवाने का इंतजाम करेगी। यह घोषणा ऐसे समय में हुई है, जब देश कोरोना महामारी की दूसरी लहर से उबरने की प्रक्रिया में है, लेकिन खतरा टला नहीं है। दूसरी लहर के उतार के बीच जो थोड़ा–बहुत समय हमें मिला है, उसका सर्वश्रेष्ठ इस्तेमाल नहीं किया गया तो फिर से मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इसीलिए अगर प्रधानमंत्री ने खुद सामने आकर देश को यह बताया है कि वह सरकार की टीका नीति में महत्वपूर्ण बदलाव कर रहे हैं तो यह निश्चित रूप से एक शुभ संकेत है। काफी समय से यह मांग की जा रही थी कि पल्स पोलियो मुहिम समेत अब तक के तमाम टीकाकरण अभियानों की तरह कोरोना का टीका भी सबको मुफ्त लगाया जाना चाहिए। यह लोगों को सरकार की ओर से किसी तरह की सुविधा या सामान मुफ्त देने की बात नहीं थी। यह उनका जीवन और स्वास्थ्य सुरक्षित करने का मामला था, जो उनका संवैधानिक अधिकार है। इतना ही नहीं, अर्थव्यवस्था के लिहाज से देखा जाए तो भी सबको सुरक्षित किए बगैर देश की आर्थिक तरक्की सुनिश्चित नहीं की जा सकती।

साफ है कि यह फैसला महामारी के खिलाफ जंग में मील का पत्थर साबित हो सकता है। टीका खरीदने की कथित लिबरलाइज्ड पॉलिसी से जो गफलत पैदा हुई थी, ताजा घोषणा से वह भी दूर हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पॉलिसी की तीखी आलोचना की थी। अलग–अलग कीमतों से भ्रम और असमंजस तो पैदा हो ही रहा था, राज्यों पर अलग से टीके खरीदने की जिम्मेदारी डालने से परस्पर दोषारोपण की प्रक्रिया भी बहुत तेज हो गई थी। राज्य शिकायत कर रहे थे कि उन्हें कंपनियां जरूरत से काफी कम टीका दे रही हैं। इस बीच, राज्यों ने टीका खरीदने के लिए जो ग्लोबल टेंडर दिए, उनका भी कोई नतीजा नहीं निकला। इसलिए केंद्र से राज्यों की ओर से टीका खरीदने की अपील की थी। अब जब केंद्र सरकार ने यह साफ कर दिया है कि राज्यों के हिस्से की ओर से भी वही वैक्सीन खरीदेगी तो किसी संदेह या असमंजस की गुंजाइश नहीं रही। इसी मौके पर प्रधानमंत्री द्वारा गरीब कल्याण अन्न योजना को दीपावली तक बढ़ाने की घोषणा भी महत्वपूर्ण है।

कोरोना की दूसरी लहर के दौरान भी बड़े पैमाने पर उद्योग– धंधों और रोजगार पर बुरा असर हुआ। ऐसे में इस पहल से देश की 80 करोड़ गरीब और जरूरतमंद आबादी को बड़ी राहत मिलेगी। कुल मिलाकर देखें तो सोमवार को हुई घोषणा सरकार की नीतियों में ऐसा संशोधन है, जो महामारी के खिलाफ हमारी मोर्चेबंदी को मजबूत करेगा।

धर्म–कर्म

अशोक वोहरा।

धर्म-दर्शन

बादल बरसने पर जरा एक किसान की आंखों में, उसके दिल में झांक कर देखिए, आपको वहां पर उमंग, उत्साह व प्रसन्नता का सागर उमड़ता दिखाई देगा। लेकिन बदलते वक्त के साथ वर्षा जल की अहमियत केवल खेतीकृबाड़ी के लिए ही नहीं, वरन् पेयजल की दृष्टि से भी बढ़ गई है। माना जा रहा है कि वर्षा 2050 तक दुनिया में पेयजल को लेकर बड़ी मारामारी मचने वाली है। बहुत से धर्म, कर्म या रिवाज ऐसे हैं जो हिन्दू धर्मग्रंथों के अनुसार सही नहीं है, जैसे सती प्रथा, दहेज प्रथा, मूर्ति स्थापना और विसर्जन, माता की चौकी, अनावश्यक व्रत–उपवास और कथाएं, पशु बलि, जादू–टोना, तंत्र–मंत्र, छुआछूत, ग्रह–नक्षत्र पूजा, मृतकों की पूजा, चार धाम को छोड़कर अन्य अधार्मिक तीर्थ–मंदिर, 16 संस्कारों को छोड़कर अन्य संस्कार आदि।

संपादकीय

अपने–अपने दावे

पूर्व गृहमंत्री और बीजेपी के विधायक बृजमोहन अग्रवाल का कहना है, ‘इस सरकार की गलत नीतियों के कारण, माओवादियों के प्रति सहानुभूति के कारण नक्सली गतिविधियां बढ़ी हैं। इसके लिए अगर कोई दोषी है तो वह कांग्रेस की सरकार है। ये नक्सलियों के समर्थन से ही सरकार में आए हैं।’ केंद्रीय गृह मंत्रालय ने छह राज्यों के आठ जिलों को अब ‘डिस्ट्रिक्ट ऑफ कंसर्न’ बताया है। इनमें छत्तीसगढ़ के तीन जिले कबीरधाम, कोंडागांव और मुंगेली शामिल हैं। अन्य जिलों में बिहार का औरंगाबाद, झारखंड का गढ़वा, केरल का वायनाड, मध्य प्रदेश का मंडला और ओडिशा का कोरापुट शामिल है। माओवादी हिंसा में पिछले सालों में उतार–चढ़ाव होता रहा है, लेकिन सुरक्षाबलों के दबाव में पीछे हट कर, हर बार अपनी ताकत को मजबूत करके हमला करने की माओवादियों की गुरिल्ला रणनीति को जानने वाले इसे कोई बड़ी सफलता की तरह नहीं देखते। वैसे माओवादी हिंसा से सर्वाधिक प्रभावित राज्य छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का मानना है कि सुरक्षाबलों के लगातार दबाव के कारण माओवादियों को कुछ ही इलाकों में सिमटना पड़ा है। वह कहते हैं, ‘नक्सलियों को हमने काफी पीछे धकेल दिया है। वे अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं।’ साइकोलॉजिकल वॉर में बेहद चालाक माओवादियों के इस दावे का सच–झूठ समझ पाना आसान नहीं है, लेकिन अभी माओवादियों की विदाई के लिए सुरक्षाबलों को लंबा संघर्ष करना पड़ेगा, यह तो तय है।

भारत में माओवादियों को शायद अंतहीन गुरिल्ला लड़ाई का प्रशिक्षण और भरोसा ही जिंदा रखे हुए है, नहीं तो पिछले पचास सालों में सैकड़ों बार इस आंदोलन के खत्म हो जाने की घोषणा की जा चुकी है।

टीके का इंतजाम

आलोक प्रकाश।।

माओवादियों की केंद्रीय कमेटी के प्रवक्ता अभय की 7 जुलाई 2021 की एक विज्ञप्ति की आखिरी लाइन है, ‘संघर्ष के सिवा जनता के न्यूनतम नागरिक और जनवादी अधिकारों को बचाया नहीं जा सकता और संघर्ष के सिवा कोई चारा नहीं है।’ भारत में माओवादियों को शायद अंतहीन गुरिल्ला लड़ाई का प्रशिक्षण और भरोसा ही जिंदा रखे हुए है, नहीं तो पिछले पचास सालों में सैकड़ों बार इस आंदोलन के खत्म हो जाने की घोषणा की जा चुकी है। तब भी, जब 1967 के नक्सलवादी आंदोलन को तीन–चार सालों के भीतर ही कुचल दिया गया था और तब भी जब किशनजी या आजाद जैसे माओवादी मारे गए। शीर्ष माओवादी नेताओं के आत्मसमर्पण के बाद भी ऐसे ही दावे होते हैं और यह सिलसिला अब भी जारी है।

कोरोना के कारण जब माओवादियों की केंद्रीय कमेटी के सदस्य हरिभूषण या विनोद की मौत की खबर आई तो एक बार फिर सैकड़ों माओवादियों के गंभीर रूप से बीमार होने के साथ ऐसे भी कयास लगने लगे कि क्या कोरोना माओवादियों के पूरे आंदोलन को निगल जाएगा? लेकिन इन अटकलों के साथ–साथ माओवाद प्रभावित इलाकों से ऐसी खबरें भी आने लगीं कि माओवादी अपने लिए कोरोना की दवाओं और टीके का इंतजाम

करने में सफल रहे हैं।

खबरों की मानें तो माओवादी जिस तरह अपनी दूसरी जरूरतों को पूरा करते रहे हैं, उसी तरह शहरी नेटवर्क और ग्रामीण इलाकों में काम करने वाले स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं पर दबाव बना कर उन्होंने दवा और कोरोना का टीका भी हासिल कर लिया। कुछ इलाकों में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं से दवा और टीका लूटने की भी खबरें आईं, लेकिन इनकी पुष्टि नहीं हो पाई। माओवादियों की लगभग हरेक टीम में दवा और छोटे–मोटे शल्य चिकित्सा के जानकार होते हैं। खुफिया सूत्रों की मानें तो कोरोना के ताजा हमले के बाद माओवादियों की टीम के चिकित्सा व्यवस्था के जानकारों की जिम्मेवारी और बढ़ गई है।

यूं तो बस्तर के इलाके में पुलिस ने बीमार माओवादियों को समर्पण के लिए प्रेरित करने की लगातार कोशिश की। समर्पण करने वाले माओवादियों का इलाज भी किया गया, लेकिन कोरोना से हुई लगभग दर्जन भर मौतों के बाद भी माओवादी अपने कैडर को आत्मसमर्पण से रोकने में सफल रहे हैं। यह सही है कि पिछले कुछ सालों में छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके में सुरक्षा बलों की तगड़ी कार्रवाई और घेराबंदी के कारण माओवादी मुश्किल में आए हैं। माओवादियों ने तो पिछले कुछ महीनों में अपने ठिकानों पर ड्रोन से बम गिराए जाने के भी आरोप लगाए हैं, जबकि पुलिस इससे इनकार करती आई है। ड्रोन से जंगल के भीतर निगरानी से भी उनकी परेशानी बढ़ी है। माओवादियों के दस्तावेज बताते हैं कि गढ़चिरौली में माओवादी विरोधी अभियान से जुड़े लोगों ने माओवादियों की ओर से मंगाए गए एक रेडियो में जीपीएस ट्रैकर लगा कर उन्हें भेज दिया और बाद में उनकी लोकेशन के आधार पर हमला किया, जिसमें कई माओवादी मारे गए।

माओवादियों की केंद्रीय कमेटी का सुरक्षाबलों को लेकर हाल का यह बयान उनके डर को उजागर करता है, ‘दुश्मन हमारी आपूर्ति व्यवस्था में घुसकर इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल वस्तुओं जैसे कंप्यूटर्स, प्रिंटर्स, रेडियोज, पावर बैंक, सोलर प्लेट, वॉकी–टॉकी आदि के भीतर जीपीएस ट्रैकर्स लगा कर भेज रहा है।’

तकनीक के मोर्चे पर माओवादियों की यह हार सरकार के लिए सुखद हो सकती है, लेकिन सच यह भी है कि इसी दौरान नक्सलियों ने देश के दूसरे हिस्सों में भी अपने पैर फैलाए हैं।

सूडोकु नवताल-5407

मध्यम

6	9			7	4		8	
	8	5	6	2			4	9
7						6		3
	3	9	5				1	
1				8				5
	6				2	9	3	
4		7						2
8	2			5	9	1	7	
	1		2	3			5	8

- प्रत्येक पंक्ति में 1 से 9 तक के अंक भरे जाने आवश्यक हैं.
- प्रत्येक आड़ी और खड़ी पंक्ति में एवं 3×3 के वर्गों में किसी भी अंक की पुनरावृत्ति न हो इसका विशेष ध्यान रखें.
- पहले से मौजूद अंकों को आप हटा नहीं सकते.
- पहेली का केवल एक ही हल है.

सूडोकु नवताल -5406 का हल

6	5	3	9	1	7	2	8	4
9	1	8	2	6	4	3	7	5
7	4	2	5	3	8	1	9	6
3	7	1	6	9	2	4	5	8
8	6	9	1	4	5	7	2	3
5	2	4	8	7	3	9	6	1
2	9	5	4	8	1	6	3	7
4	3	6	7	5	9	8	1	2
1	8	7	3	2	6	5	4	9

अपना ब्लॉग

नई कमिटी बना कर इलाका विस्तार शुरू

मोहन। माओवादियों ने पिछले कुछ सालों में एमएमसी यानी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जोन नाम से अपनी नई कमिटी बना कर इलाका विस्तार शुरू किया है। पीपल्स वॉर ग्रुप के दौर में जिन जिलों पर माओवादियों की पकड़ पहले मजबूत थी, उन्होंने फिर से उनमें अपनी जमीन तलाशनी शुरू की है। पिछले कुछ दिनों में कान्हा नैशनल पार्क से लगे हुए इलाके में मुठभेड़ हुई हैं और भोपाल तक माओवादियों को हथियार की सप्लाई करने वाले लोग पकड़े गए हैं। सरकार और विपक्ष के इन दावों से अलग माओवादी, फिलहाल तो 28 जुलाई से 3 अगस्त तक बस्तर के अलग–अलग इलाकों में शहीद स्मृति सप्ताह के आयोजन में जुटे हुए हैं और उनका अपना दावा है, ‘पिछले कुछ महीनों में हमारी सैन्य क्षमता बढ़ी है और हम मजबूत हुए हैं।’ तमाम दावों के बाद भी गृह मंत्रालय की सूची में छत्तीसगढ़ के बस्तर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, कांकेर, नारायणपुर, राजनांदगांव और सुकमा देश के सर्वाधिक माओवाद प्रभावित जिले बने हुए हैं।